



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]  
No. 61]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2004/चैत्र 6, 1926  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2004/CHAITRA 6, 1926

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण  
अधिसूचना

मुंबई, 22 मार्च, 2004

सं. टीएमपी/31/2003-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 54 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी निदेश के अनुपालन में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार बालार्ड पायर से चलने वाले नावों, क्राफ्टों, बाजों और लांचेज द्वारा जल दुलाई के लिए देय लाइसेंस शुल्क से संबंधित मुम्बई पत्तन न्यास के दरों के मान में संशोधन करता है।

अनुसूची

(मामला सं० टीएमपी/31/2003-एमबीपीटी)

आदेश

(मार्च, 2004 के 15वें दिन पारित किया गया)

इस प्राधिकरण ने संयुक्त टॉवेज और पायलिटिज प्रभारों से संबंधित मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के एक प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 30 नवम्बर, 1998 को एक आदेश पारित किया था। तत्पश्चात्, एमबीपीटी द्वारा प्रस्तावित टॉवेज और पायलिटिज प्रभारों में संशोधित प्रावधानों की एक व्यापक सूची 13 जनवरी, 1999 को अधिसूचित की गई थी। इन अधिसूचनाओं के अनुसार, बालार्ड पायर से प्रचालन कर रहे लांचेज जल दुलाई के लिए 50/-रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह की दर पर लाइसेंस शुल्क लगाए जाने के शर्ताधीन हैं।

2. बाद में, मुम्बई शिप-टू-शोर लांच ओनर्स एसोसिएशन (एमएसएसएलओए) ने एमबीपीटी के दरों के मान के अनुसार जल दुलाई के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान के संबंध में इस प्राधिकरण के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। इस प्राधिकरण ने एमबीपीटी और एमएसएसएलओए सहित प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकायों के साथ सामान्य विचार-विमर्श के बाद जल दुलाई के लिए लाइसेंस शुल्क में कमी के लिए एमएसएसएलओए के अभ्यावेदन को रद्द करते हुए 14 दिसम्बर, 2001 को कारण स्पष्ट करते हुए एक आदेश (स्पीकिंग आर्डर) पारित किया था। लेकिन, एमबीपीटी के प्रशुल्कों के अगले सामान्य संशोधन के समय संबंधित शुल्क की वसूली के प्रयोजनार्थ पुनः वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने का निर्णय किया गया था।

3. तत्पश्चात्, एमएसएसएलओए ने इस प्राधिकरण के दिनांक 14 फरवरी, 2001 के आदेश के विरुद्ध माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल कर दी थी। इस बीच, पोत-संबद्ध प्रभारों के संशोधन से संबंधित एमबीपीटी के प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2004 के आदेश द्वारा निर्णय किया गया था। जल ढुलाई प्रभारों के संदर्भ में उक्त आदेश में निम्नलिखित टिप्पणिया की गई हैं :-

“एमएसएसएलओए ने जल ढुलाई के लिए वर्तमान लाइसेंस शुल्क (50/-रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह) के विरुद्ध मुम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है और यह समझा जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 54 के अधीन आवश्यक राहत के लिए केन्द्रीय सरकार से संपर्क करने का निदेश दिया है। सरकार द्वारा अभ्यावेदन के निपटान तक, यह परामर्श दिया जाता है कि बालार्ड पायर से लांचेज प्रचालनों, जोकि कि प्रसंगवश मुम्बई पत्तन न्यास का भी प्रस्ताव है, के संदर्भ में यथास्थिति बनाई रखी जाए।”

तदनुसार, संशोधित दरों के मान में बालार्ड पायर से प्रचालन कर रहे लांचेज के संबंध में 50/-रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह की वर्तमान दर को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। लेकिन, अपोलो बंडर और न्यू फैंरी व्हार्फ से प्रचालन कर रहे लांचेज के संबंध में एमबीपीटी द्वारा प्रस्तावित 25/-रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह की दर इस प्राधिकरण के दिनांक 9 जनवरी, 2004 के आदेश में अनुमोदित की गई थी।

4.1 भारत सरकार, नौवहन मंत्रालय ने अपने दिनांक 3 अक्टूबर, 2003 के पत्र द्वारा इस प्राधिकरण को सूचित किया था कि एमएसएसएलओए ने माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 54 के अधीन इस प्राधिकरण के आदेश को संशोधित अथवा रद्द करने के लिए केन्द्रीय सरकार से संपर्क किया है, ताकि जल ढुलाई के लिए लाइसेंस शुल्क कम किया जा सके और अपोलो बंडर तथा न्यू फैंरी व्हार्फ से प्रचालन कर रहे अन्य लांच स्वामियों से वसूल किए जा रहे 10/-रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह (50/-रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह की बजाय) के समान दरें वसूल की जा सकें और उक्त कम की गई दरें पूर्व-प्रभाव से वसूल की जाएं। इसके अलावा, नौवहन मंत्रालय ने अपने दिनांक 16 जनवरी, 2004 के पत्र द्वारा माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में इस प्राधिकरण को सूचित किया था, जिसमें केन्द्रीय सरकार को एमएसएसएलओए के अभ्यावेदन पर निर्णय करने का निदेश दिया गया था और केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित निर्णयों के अनुसार इस प्राधिकरण के दिनांक 27 अक्टूबर, 1998 और 13 जनवरी, 1999 के आदेशों के साथ अधिसूचित दरों के मान को संशोधित करने के लिए इस प्राधिकरण को निदेश दिया गया था :-

- (i) बालार्ड पायर में जल ढुलाई प्रभारों की दरें भविष्य में अपोलो बंडर और न्यू फैंरी व्हार्फ की दरों के बराबर की जाएं।
- (ii) विगत अवधि अर्थात् 30 दिसम्बर, 1998 से नई दरें निर्णीत होने की तारीख तक बालार्ड पायर लांच स्वामियों से वसूल की गई दर 50/-रुपए से घटाकर 25/-रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह कर दी जाएं।

4.2 तत्पश्चात्, नौवहन मंत्रालय ने सचिव (नौवहन) द्वारा पारित आदेश की एक प्रति प्रेषित की और निम्नलिखित की पुष्टि की थी :-

- (i) दरों के मान को संशोधित करने का निदेश महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 54 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा जारी किया गया है और यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसरण में है।
- (ii) बालार्ड पायर में जल ढुलाई प्रभारों की नई दरें भविष्य के लिए तत्काल निर्धारित की जाएं।
- (iii) 30 दिसम्बर, 1998 से नई दरें निर्णीत होने की तारीख तक बालार्ड पायर लांच स्वामियों से वसूल की गई दर 50/-रुपए से घटाकर 25/-रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह कर दी जाएं।

5. महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 54 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेश के अनुपालन में और बालार्ड पायर जेट्टी से चलने वाले नावों, क्राफ्टों, बाजों और लांचेज के संबंध में जल दुलाई प्रभारों के लिए दरों के मान से संबंधित इस प्राधिकरण के 27 अक्टूबर, 1998 के आदेश, 13 जनवरी, 1999 की अधिसूचना और 9 जनवरी, 2004 के आदेश के अधिक्रमण में यह प्राधिकरण 2.1. पायलिटिज, टग सहायता, टॉवेज और अन्य सेवाओं से संबंधित एमबीपीटी के दरों के मान में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

(i) खंड सं० 2.1.12 में तालिका सं०-11 (जल दुलाई के लिए लाइसेंस शुल्क) के क्रम सं० 2 में प्रावधान को हटाया जाता है और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जोकि भारत के राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा :-

“(2) बालार्ड पायर जेट्टी से चलने वाले  
नाव, क्राफ्ट, बाज और लांचेज

25/-रुपए”

(ii) बालार्ड पायर जेट्टी से चलने वाले नावों, क्राफ्ट, बाजों और लांचेज के लिए जल दुलाई लाइसेंस शुल्क को 30 दिसम्बर, 1998 से पूर्व-प्रभाव से उपर्युक्त (i) में उल्लिखित जल दुलाई के लिए लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरों के क्रियान्वयन की प्रभावी तारीख तक 50/-रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह से घटकर 25/-रुपए प्रति जीआरटी प्रतिमाह किया जाता है ।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[ विज्ञापन/III/TV/143/03/असाधारण ]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd March, 2004

**No. TAMP/31/2003-MBPT.**—In compliance of a direction issued by the Government of India under Section 54 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Tariff Authority for Major Ports hereby modifies the Scale of Rates of the Mumbai Port Trust relating to Licence Fees for Water Conveyance payable by boats, crafts, barges and launches plying from the Ballard Pier Jetty as in the Order appended hereto.

### SCHEDULE

**No. TAMP/31/2003-MBPT**

## ORDER

(Passed on this 15<sup>th</sup> day of March 2004)

This Authority had notified an order on 30 November 1998 in respect of proposal of the Mumbai Port Trust (MBPT) relating to composite towage and pilotage charges. Thereafter, a comprehensive listing of the amended provisions in the towage and pilotage charges proposed by the MBPT was notified on 13 January 1999. As per these notifications, the launches operating from Ballard Pier are subjected to a levy of license fee for Water Conveyance at Rs. 50 per GRT per month.

2. Subsequently, Mumbai Ship to Shore Launch Owners Association (MSSLOA) filed a representation before this Authority relating to payment of license fee for Water Conveyance as per the MBPT Scale of Rates. This Authority after usual consultation with the MBPT and representative bodies of users including MSSLOA had passed a speaking order on 14 December 2001

rejecting the representation of the MSSLOA for a reduction in the license fee for Water Conveyance. But, it was decided to examine the issue of re-categorisation for the purpose of charging the concerned fee at the time of the next general revision of tariff at MBPT.

3. Thereafter, MSSLOA filed a Writ Petition against this Authority's order dated 14 February 2001 in the Hon'ble High Court At Mumbai. In the meanwhile, the MBPT proposal for revision of vessel related charges was decided by this Authority vide order dated 9 January 2004. With reference to revision of Water Conveyance Charges the following observations have been made in that Order:

*"The MSSLOA has filed a Writ Petition in the High Court of Bombay against the existing license fee for Water Conveyance ( Rs. 50 per GRT per month ) and it is understood that the Hon'ble High Court has directed the petitioners to approach the Central Government for necessary relief under Section 54 of the MPT Act. Till disposal of the representation by the Government, it is advisable to maintain status-quo with reference to the launches operating from Ballard Pier which incidentally is the proposal of the Mumbai Port Trust also".*

Accordingly, the existing rate of Rs. 50 per GRT per month was allowed to continue in the revised Scale of Rates in respect of launches operating from Ballard Pier. But, the rate of Rs.25/- per GRT per month in respect of launches operating from Apollo Bunder and New Ferry Wharf proposed by the MBPT was approved in the Authority's Order dated 9 January 2004.

4.1 The Government of India in the Ministry of Shipping (MOS) vide its letter dated 3 October 2003 informed this Authority that the MSSLOA had, in pursuance of order of Hon'ble High Court at Bombay, approached the Central Government to modify or cancel the Authority's order under Section 54 of Major Port Trusts Act, 1963 (M.P.T. Act) to reduce the license fee for Water Conveyance and bring it at par with the rates charged to other launch owners operating from Apollo Bunder and New Ferry Wharf at Rs. 10 per GRT per month ( instead of Rs. 50 per GRT per month ) and to charge the said reduced rates retrospectively. Further, the MOS vide its letter dated 16 January 2004 informed this Authority about the order of the Hon'ble High Court at Bombay directing the Government of India to decide the representation of MSSLOA and directed this Authority to modify the Scale of Rates notified with the Authority's order dated 27 October 1998 and 13 January 1999, in accordance with the following decisions of the Central Government:

- (i). The rates of Water Conveyance Charges at Ballard Pier may be made at par with those for Apollo Bunder and New Ferry Wharf in future.

- (ii). For the past period, i.e., from 30 December 1998 to the date of new rates are decided, the rates charged from Ballard Pier launch owners may be reduced from Rs.50/- to Rs.25/- per GRT per month.

4.2 Subsequently, the MOS furnished a copy of the order passed by the Secretary (Shipping) and confirmed the following:

- (i). The direction to modify the Scale of Rates is issued by the Government in exercise of powers conferred by Section 54 of MPT Act, 1963 and in pursuance of directions given by the Hon'ble High Court.
- (ii). New rates of Water Conveyance Charges at Ballard Pier be prescribed immediately for future.
- (iii). From 30 December 1998 to the date new rates are decided rates charged from Ballard Pier launch owners may be reduced from Rs. 50/- per GRT per month to Rs.25 per GRT per month.

5. In compliance with the direction given by the Central Government under Section 54 of MPT Act and in supersession of this Authority's order dated 27 October 1998, Notification dated 13 January 1999 and Order dated 9 January 2004 relating to the Scale of Rates for Water Conveyance Charges in respect of Boats, Crafts, Barges and Launches plying from the Ballard Pier Jetty, this Authority makes the following modifications in the Scale of Rates of the MBPT relating to 2.1. Fees and charges for pilotage, tug assistance, towage and other services:

- (i). The provision at Sl. No. 2 of Table No. II (License Fees for Water Conveyance) in clause No. 2.1.12 is deleted and substituted by the following, which shall come into force from the date of publication of the order in the Gazette of India:

“(2) Boats, Craft, Barges and Launches Rs.25”  
plying from Ballard Pier Jetty

- (ii). The license fee for Water Conveyance for Boats, Craft, Barges and Launches plying from the Ballard Pier Jetty is reduced from Rs. 50 per GRT per month to Rs. 25 per GRT per month retrospectively from 30 December 1998 till the effective date of implementation of the modified rates of license fee for Water Conveyance as mentioned at (i) above.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT./III/IV/143/03-Exty.]

1006 57 mny